(क) क्या रेलवे बोर्ड ने सतना, रीवा, बघवार, ब्योहारी रेल लाइन के रीवा, बघवार, ब्योहारी खंड का निर्माण-कार्य अपने हाथ में न लेने का निर्णय लिया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) उक्त रेल लाइन के सतना, रीवा और ब्योहारी खंड पर अगले दस वर्षों के दौरान माल और यात्री परिवहन के संबंध में कुल कितना आकलन किया गया है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा उक्त रेल लाइन के रीवा और ब्योहारी खंड का निर्माण-कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंगा) : (क) संसाधनों की तंगी के कारण ऐसे रेल संपर्क के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) सतना-रीवा-बघवार-ब्योहारी सर्वेक्षण रिपोर्ट 1990 के अनुसार अगले 10 वर्षों के लिए माल और यात्री यातायात से संबंधित अनुमान नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	प्रत्येक दिशा में यात्री गाड़ियों की संख्या	प्रत्येक दिशा में यात्रियों की संख्या	प्रत्येक दिशा में मालगाड़ियों की संख्या	प्रत्येक दिशा में माल डिब्बों की संख्या	जोड़ गाड़ियां प्रत्येक दिशा में
पहला वर्ष	2.0	798	2.88	216	4.88
छठा वर्ष	2.0	2393	4.18	314	6.18
ग्यारहवां वर्ष	2.0	2870	4.27	320	6.27

44 करोड़ रुपये की लागत पर सतना-रीवा रेल लाइन (50 कि॰मी॰) को पूरा कर लिया गया है । रीवा-ब्योहारी नई रेल लाइन (71.67 कि॰मी॰) के निर्माण पर 75 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है ।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार रेलवे लाइनें उत्तरोत्तर और अधिक क्षेत्रों तक बढ़ायी जा रही हैं जिसके लिए प्राथमिकताएं संभावित यातायात-क्षमता और राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार तय की जाती हैं ।

पश्चिम रेलवे के लिए माल डिब्बे उपलब्ध कराया जाना

1258. श्री अजीत जोगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे को, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कितने माल डिब्बे उपलब्ध कराए गए और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त में पश्चिम रेलवे के पास कितने माल डिब्बे उपलब्ध थे ;

(ख) वर्कशाप में मरम्मत के लिए कितने माल डिब्बे भेजे गए और उनमें से कितने माल डिब्बों की मरम्मत की गई ;

(ग) 30 जून, 1992 की स्थिति के अनुसार कितने माल डिब्बों को काम के लिए अनुपयुक्त घोषित किया गया है; और

(घ) सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माल डिब्बों की खरीद तथा पश्चिम रेलवे के लिए माल ढुलाई हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंगा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम रेलवे पर माल डिब्बों (चौपहियों में) के बेड़े के लिए वैनिक औसत लक्ष्य और वास्तविक बेड़ा इस प्रकार है :

आमान	लक्ष्य	बेड़ा (संख्या)
बड़ी लाइन	39200	42017
मीटर लाइन	22500	22570

(ख) और (ग) 30-6-92 को समाप्त तिमाही के लिए चौपहियों के संबंध में सूचना इस प्रकार है :

(1)	मरम्मत के लिए भेजे गए माल डिब्बों की संख्या	3919
(2)	मरम्मत किए गए माल डिब्बों की संख्या	3788
(3)	नाकारा घोषित किए गए माल डिब्बों की संख्या	505

(घ) माल डिब्बों के प्रापण की योजना समूची भारतीय रेलों के लिए बनाई जाती है न कि रेलवेवार पृथक-पृथक रेलों की आवश्यकताएं इस कामन पूल से पूरी की जाती हैं । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,20,000 माल डिब्बों के प्रापण की योजना है । ये माल डिब्बे माल यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न समयों पर विभिन्न रेलों को भेजे जाएंगे ।

Konkan Railway re-alignment

1259. SHRI H. HANUMANTHAPPA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an agitation going on for and against Konkan Railway re-alignment;

(b) what is the reaction of Government; and

(c) the details of steps taken by Government to solve the Kokan Railway issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A One-man High Level Committee consisting of Justice G. J. Oza, retired Judge of Supreme Court of India has been appointed to look into the various issues relating to alignment of Konkan Railway line passing through Goa (Mayem-Bali) for a final decision.

Tender for manufacture by N.E. Railway Administration

1260. SHRI BRAHMADEO ANAND PASWAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the N.E. Railway Administration has awarded the tender for manufacture, stocking, supply and loading of hand broken stone, from Railway quarry at Jamalpur to the highest bidder, black listed parties;

(b) whether there was another lowest bidder belonging to scheduled caste whose case was ignored;

(c) what were the claims of lower bidders;

(d) whether the policy of the Railway for giving preference to scheduled castes/scheduled tribes has been dispensed with; and

(e) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) No such tenders were awarded to the highest bidder and blacklisted parties.

(b) The lowest tender was ignored due to unsatisfactory past performance and inadequate credentials.

(c) There were no claims.

(d) and (e) As per Railway Policy tenders are decided only on merits of each case and not on the basis of religion, caste and creed.

Amount Spent on Advertisement by Railways

1261. SHRI MOHAMMAD AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state what are the details of the amount spent by Railways on advertisement during the period from 1st April, 1992 to 31st March, 1993, language and zone-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K. C. LENKA): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Re-alignment of route of Konkan Railway in Goa

1262. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to a dispute for the re-alignment of route for 34 km of the 105 km route in Goa, the on-going work in the disputed sector has been suspended;

(b) if so, what steps Government have taken to end this dispute so that the work in that sector could start to end delay;

(c) whether final alignment of route in Goa has been dicided upon, if so, the details thereof;

(d) whether there is any financial difficulty for completion of this disputed sector of the route; if so, the measures taken to tackle it; and

(e) whether any step would be taken to ensure that the entire Konkan Railway Project will be completed by the stipulated date viz., October 1994?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. K. JAFFER SHARIEF): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A one-man High Level Committee consisting of Justice G. J. Oza, retired Judge of Supreme Court of India has been appointed to look into the various issues relating to alignment of Konkan Railway line passing through Goa. The alignment will be decided after the report of this Committee is received.

(d) There has been no special financial difficulty for the disputed sector. However, KRC has been facing shortage of funds mainly on account of the poor market conditions for tax-free bonds. With a view to providing more funds to the KRC, it has been decided to raise the equity base from Rs. 400 crores to Rs. 600 crores.